



वी. चेट्टियार

कार्यकारी संपादक
8898800908

हिन्दी साप्ताहिक

RNI No.: MAHHIN/2023/89178

एकता केसरी

EKTA KESARI

Issue: 2 • Volume: 13 • Hindi Weekly • Mumbai, Friday 25 April to 01 May 2025 • Price 5/- • Page 8

पहलगाम अटैक: कश्मीर में फंसे पर्यटकों के लिए एक्शन में आए फडणवीस, हेल्पलाइन पर संपर्क करने की अपील

मुंबई: जम्मू कश्मीर में पहलगाम आतंकी हमले के बाद राज्य के टूरिस्ट को वापस लाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री फडणवीस की अगुवाई वाली सरकार ने लोगों से अपील की है कि कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में फंसे लोगों की जानकारी राज्य आपदा प्रबंधन कक्ष के 022-22027990 दूरभाष नंबर पर उपलब्ध कराएं, ताकि पर्यटक के तौर कश्मीर गए लोगों को सुरक्षित वापस लाया जा सके। मुंबई से आगे

भेजी जाएंगी डेडबॉडी राज्य सरकार ने बयान में कहा है कि पहलगाम हमले की पृष्ठभूमि में मंत्रालय स्थित आपदा प्रबंधन कक्ष चौबीसों घंटे कार्यरत है। इस हमले में मारे गए पर्यटकों की डेडबॉडी श्रीनगर से मुंबई लाए जा रही हैं। महाराष्ट्र और गुजरात के मृतकों के शव विमान से मुंबई हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। वहां से उन्हें एम्बुलेंस द्वारा उनके संबंधित स्थानों तक भेजा जाएगा। इस प्रक्रिया में सभी आवश्यक सहायता राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है। आपदा



प्रबंधन नंबर पर करें फोन कश्मीर में फंसे पर्यटक और महाराष्ट्र में मौजूद उनके परिजन किसी भी प्रकार की सहायता के लिए 022-22027990 नंबर पर तुरंत संपर्क करें, ऐसा आग्रह राज्य आपदा प्रबंधन कक्ष द्वारा किया गया है। सरकार की तरफ से कश्मीर (श्रीनगर) के आपातकालीन संपर्क नंबर भी साझा किए गए हैं। पर्यटकों की सहायता हेतु श्रीनगर जिला प्रशासन द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय में 24x7 हेल्प डेस्क/ आपातकालीन शेष पृष्ठ २ पर

मुंबई के मानखुर्द में सिलेंडर विस्फोट से लगी आग, 10 साल की मासूम समेत 2 की मौत

मुंबई के मानखुर्द के मंडला इलाके में सोमवार रात को सिलेंडर विस्फोट से आग लग गई। इस हादसे में 10 वर्षीय बच्ची खुशी खान और 25 वर्षीय फराह खान की मौत हो गई। छह लोग घायल हुए हैं। मुंबई के मानखुर्द के मंडला इलाके में सोमवार (21 अप्रैल) की रात हुए आगजनी की घटना में एक 10 वर्षीय बच्ची खुशी खान और 25 साल की लड़की फराह खान की मौत हो गई।



मुंबई फायर ब्रिगेड के मुताबिक यह हादसा रात करीब 8:20 बजे हुआ। घटना की सूचना मिलते ही मुंबई फायर ब्रिगेड की गाड़ियां,

एंबुलेंस और पुलिस कर्मी मौके पर पहुंचे। यह आग मानखुर्द मंडला इलाके में जनता नगर में एक छोटे घर में सिलेंडर विस्फोट के कारण लगी

थी। आग पर रात करीब साढ़े 11 बजे काबू पा लिया गया। शताब्दी अस्पताल में कराया गया भर्तीफायर कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के मुताबिक, इस हादसे में कम से कम छह लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को बीएमसी द्वारा संचालित गोवंडी के शताब्दी अस्पताल में भर्ती कराया गया। महानगर पालिका और मुंबई पुलिस हादसे की वजह जानने की लिए जाँच कर रही है। घायलों को कराया गया अस्पताल में भर्ती मुंबई

शेष पृष्ठ २ पर

धर्म पूछकर पर्यटकों को मारा... पहलगाम हमले के विरोध में शिवसेना ने जलाए पाकिस्तान के झंडे



मुंबई: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम आतंकी हमले में पर्यटकों को धर्म के आधार पर निशाना बनाए जाने के बाद देश भर में आक्रोश है। शिवसेना नेता संजय निरुपम ने केंद्र सरकार से मांग की है कि पहलगाम में निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाने वाले आतंकवादियों को घर में पाकिस्तान में घुसकर मार देना चाहिए। एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के नेता संजय शेष पृष्ठ २ पर

महाराष्ट्र चुनाव कोई गड़बड़ी नहीं... राहुल गांधी के अमेरिका में दिए बयान के बाद चुनाव आयोग ने जारी किए आंकड़े

मुंबई: महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के बाद मतदाता सूची और मतदान प्रक्रिया को लेकर लगाए जा रहे आरोपों पर भारतीय चुनाव आयोग ने जवाब दिया है। आयोग के स्पष्टीकरण के अनुसार, चुनाव प्रक्रिया में कोई त्रुटि नहीं थी और चुनाव सभी कानूनी प्रावधानों के अनुसार आयोजित किए गए थे। चुनाव आयोग ने यह सफाई ऐसे वक्त

पर जारी की है जब लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने अपने विदेश दौरे में महाराष्ट्र चुनावों में गड़बड़ी का जिक्र करते हुए सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने इससे पहले दिल्ली में एमवीए के घटक दलों के नेताओं के साथ भी एक प्रेस कांफ्रेंस की थी।



कितने लोगों ने डाले वोट आयोग के अनुसार महाराष्ट्र में 6 करोड़ 40 लाख 87 हजार 588 मतदाताओं ने मतदान प्रक्रिया में भाग लिया। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे के बीच हर घंटे औसतन 58 लाख मतदाता वोट डालते हैं। हालांकि, आयोग

ने स्पष्ट किया कि यह ध्यान देने वाली बात है कि अंतिम दो घंटों में केवल 65 लाख मतदाताओं ने ही मतदान किया, जबकि अपेक्षित 116 लाख मतदाताओं ने मतदान किया था, लेकिन इससे किसी गड़बड़ी का निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता। आयोग को नहीं मिली शिकायत आयोग के अनुसार प्रत्येक मतदान केन्द्र पर शेष पृष्ठ २ पर



संपादकीय

हिंदी विरोध की सस्ती राजनीति

एक बार फिर हिंदी की पिटाई हो रही है। पहले तमिलनाडु में हुई। फिर महाराष्ट्र में। कारण बताया गया कि नई शिक्षा नीति के जरिये तमिलनाडु और महाराष्ट्र में हिंदी थोपने की साजिश की जा रही है। हिंदी को साम्राज्यवादी भाषा भी बताया जा रहा। कुछ लोग तो कहने लगे हैं कि हिंदी सांप्रदायिक भी है। एक भाषा जिसके बोलने वाले साठ करोड़ लोग हैं, उसे जब-तब धर लिया जाता है। दरअसल जब नेताओं के पास जनकल्याण के मुद्दे खत्म हो जाते हैं, तो वे इसी तरह सस्ती राजनीति के सहारे लोगों की भावनाओं को भड़काकर वोट जुटाते हैं। जनतंत्र की यह ताकत भी है और कमजोरी भी कि कोई किसी को कभी भी निशाने पर ले सकता है। लतिया सकता है, चाहे वह भाषा ही क्यों न हो। यह हिंदी के लोगों की उदारता ही कही जाएगी कि वे अपनी भाषा के अपमान को एक कड़वा घूंट समझकर झेल लेते हैं। पिछले दिनों हिंदी के बहुत से ऐसे लोगों की पोस्ट भी देखी, जो हिंदी से खाते-कमाते हैं, लेकिन हिंदी थोपने के फर्जी नैरेटिव को आगे बढ़ाते हैं। हिंदी लेखक तो प्रायः इस मसले पर कुछ बोलते ही नहीं, जबकि सच यह है कि जब तक हिंदी पढ़ने-बोलने वाले हैं, तभी तक उनकी पुस्तकें पढ़ी जा रही हैं। हिंदी विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती है तो इसीलिए कि वह रोजगार की भाषा भी है। हिंदी बोलने वालों की बड़ी आबादी को देखते हुए बड़े-बड़े कॉर्पोरेट लोगों की जेब तक पहुंचने के लिए अपने-अपने उत्पादों का विज्ञापन हिंदी में करवाते हैं। वे हिंदी के जरिये भारी मुनाफा तो कमाते हैं, लेकिन हिंदी और हिंदी भाषियों के लिए करते क्या हैं, ये वही बता सकते हैं। पूरा हिंदी फिल्म उद्योग महाराष्ट्र में है, जो वहां की सरकार की आर्थिकी को चलाने में मदद करता है, रोजगार देता है, लेकिन हिंदी जब पिटती है, तो बड़े-बड़े कलाकार खामोश हो जाते हैं। कौन आफत मोल ले, क्योंकि उनकी फिल्मों की भाषा हिंदी जरूर है, लेकिन जीवन की भाषा अंग्रेजी है। बहुत कम कलाकार हैं, जो हिंदी में बात करना पसंद करते हैं। आखिर हिंदी क्षेत्र से आने वाले कितने नेता हैं, जो हिंदी के पक्ष में बोलते हैं। हां, उन्हें हिंदी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के वोट जरूर चाहिए। लोकसभा की 50 प्रतिशत से अधिक सीटें हिंदी भाषी इलाकों से आती हैं। बड़ी संख्या में दक्षिण भारतीय फिल्मों हिंदी में डब की जाती हैं और वे खूब पैसा कमाती हैं। तब भी वहां के नेता-अभिनेता हिंदी को गरियाने में पीछे नहीं रहते। हिंदी फिर पिट रही है और सब खामोशी से देख रहे हैं। शायद इसी कारण महाराष्ट्र सरकार को पांचवीं कक्षा तक हिंदी को अनिवार्य किए जाने के फैसले से पीछे हटना पड़ा। जब से अस्मिताओं की राजनीति शुरू हुई है, हर एक को लगने लगा है कि वही महान है और उसकी भाषा महान है। अगर ऐसा है तो हिंदी वालों को कौन रोकता है कि वे भी अपनी भाषा को महान मानें, लेकिन देखा तो यह गया है कि जब कोई हिंदी क्षेत्र का व्यक्ति किसी बड़े पद पर पहुंच जाता है तो अक्सर गर्व से कहता है कि मेरा हिंदी में हाथ तंग है। अन्य भाषा-भाषियों की इसके लिए तारीफ करनी चाहिए कि वे अपनी भाषा को लेकर किसी हीनता ग्रंथि से जकड़े हुए नहीं हैं। जिस केरल में मार्क्सवादी पार्टी के बड़े नेता ईएमएस नंबूदरीपाद ने हिंदी को शिक्षा के क्षेत्र की दूसरी भाषा बनाया, वहां से भी पिछले दिनों हिंदी विरोध के सुर सुनाई दिए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सिद्धरमैया भी हिंदी विरोध की लहर पर सवार होते रहे हैं। एक बार मैसूर के कलेक्टर ने यात्रियों की सुविधा के लिए सड़कों पर कन्नड़ और अंग्रेजी के अलावा हिंदी में नाम लिखवाए, तो इतना विरोध हुआ कि हिंदी नाम हटवाने पड़े। इससे बड़ी विडंबना कोई नहीं कि अब कुछ कांग्रेस नेता भी हिंदी विरोध की राजनीति करते हैं, जबकि आजादी के संघर्ष के दौरान कांग्रेस के बड़े नेता भी हिंदी को जरूरी संपर्क भाषा मानते थे।

जिहादी आतंक का उपचार, पाकिस्तान की भी चौतरफा घेराबंदी

कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों को उनके धर्म के आधार पर निशाना बनाकर किए गए आतंकी हमले में 28 लोगों की जान चली गई और कई घायल हो गए। आतंकियों ने हत्या करने से पहले पुरुष पर्यटकों से पता किया कि वे हिंदू हैं अथवा मुसलमान? पुरुष पर्यटकों के कपड़े उतार कर यह पुष्ट किया कि वे मुस्लिम तो नहीं हैं। कुछ पर्यटकों से कलमा सुनाने की भी मांग की गई और उसे सुनाने में असमर्थ लोगों की हत्या उनकी पत्नी और बच्चों के सामने ही कर दी गई। इस आतंकी हमले की कई हृदयविदारक तस्वीरें सामने आई हैं। कहीं तीन साल का बच्चा अपने पिता के लहलुहान शव पर बैठा रो रहा है तो कहीं भारतीय नौसेना के एक अधिकारी की नवविवाहिता अपने मृत पति के शव के पास अकेली असाहाय बैठी नजर आ रही है। मृतकों एवं घायलों में खुफिया विभाग के एक अधिकारी, भारतीय नौसेना, वायु सेना आदि शामिल हैं, जो अपने परिवारों के साथ छुट्टियां मनाने पहलगाम गए थे। इसका अंदेशा है कि आतंकियों को



पर्यटन व्यवसाय से जुड़े स्थानीय लोगों ने उनके वहां होने की मुखबिरी की हो। इन आतंकियों को शरण भी स्थानीय लोगों ने दी होगी। यह पहली बार नहीं है कि स्थानीय लोगों द्वारा आतंकियों के लिए उनके लक्ष्य की निशानेदेही की गई हो। इससे पहले प्रधानमंत्री पुनर्वास पैकेज के जरिये कश्मीर में सरकारी नौकरियों पर भेजे गए कश्मीर के विस्थापित हिंदुओं की भी उनके ही साथी कर्मियों की मुखबिरी के चलते हत्या के मामले सामने आ चुके हैं। ऐसी ही भेदियों की वजह से सैन्य बलों पर भी कई हमले हो चुके हैं। कश्मीर में हिंदुओं को निशाना बनाने की यह पहली घटना नहीं। जून 2024 में रियासी में शिवखोड़ी मंदिर से लौट रहे तीर्थयात्रियों की बस पर आतंकियों ने घात लगाकर हमला किया था। उसमें

नौ तीर्थयात्रियों की मौत हो गई थी। कश्मीरी समाज में आतंकी संगठनों की पैठ कितनी गहरी है, इसे इससे समझा जा सकता है कि इस वर्ष ही जम्मू-कश्मीर सरकार के पांच कर्मचारियों को नौकरी से इसलिए निकालना पड़ा, क्योंकि सरकार में रहते हुए भी वे आतंकी संगठनों के लिए काम कर रहे थे। ऐसे और सरकारी कर्मचारी हैं, जिनकी आतंकी संगठनों से मिले होने के संदेह में जांच हो रही है। कश्मीर में फैले इस्लामी कट्टरपंथ का यह वह सच है, जो अक्सर बाकी देश की जनता तक नहीं पहुंच पाता। अनुच्छेद 370 यह सोचकर भी हटाया गया था कि देश का कोई भी नागरिक अन्य राज्यों की भांति चाहेगा तो कश्मीर में भी व्यवसाय स्थापित कर सकेगा या जब चाहे वहां

आवाजाही कर सकेगा। कश्मीर में गहराई से व्याप्त इस्लामिक कट्टरपंथ के चलते ऐसा होना आज तक संभव नहीं हो सका और पीएम पैकेज के जरिये नौकरी करने भेजे गए कश्मीर के ही मूल निवासी हिंदुओं की भी निशाना बनाकर हत्याएं हुईं। यह यही सिद्ध करता है कि कश्मीर केवल राजनीतिक या संवैधानिक समस्या नहीं है और न ही उसे पारंपरिक सैन्य कार्रवाई से नियंत्रित किया जा सकता है। कश्मीर में तब तक पूर्ण रूप से शांति स्थापित नहीं हो सकती, जब तक जिहादी कट्टरपंथ से ग्रस्त कश्मीरियों का वैचारिक उपचार न हो।

चीन अपने मुस्लिम बाहुल्य शिनजियांग प्रांत में यही कर रहा है। चीन की कम्युनिस्ट सरकार अलगाववादी एवं आतंकी विचारधारा की गिरफ्त में आ चुके लोगों को पुनर्शिक्षण कैंपों में भेजती है। इन कैंपों में ऐसे लोगों के मन-मस्तिष्क में भर चुकी कट्टरपंथी जिहादी विचारधारा को निकाला जाता है और उन्हें गैर-मुसलमानों के प्रति मानवीय संवेदनाएं रखने की शिक्षा दी जाती है।

पृष्ठ 1 का शेष

पहलगाम अटैक: कश्मीर में

नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। इनके नंबर हैं दूरभाष: 0194-2483651, 0194-2463651, 0194-2457543 इसके साथ तीन व्हाट्सएप नंबर: 7006058623, 7780805144, 7780938397 भी हैं। कुल 28 टूरिस्ट की मौत पहलगाम आतंकी हमले में महाराष्ट्र के पांच लोगों की मौत हुई है। इस हमले में अब तक कुल 28 टूरिस्ट की मौत की पुष्टि की गई है। मंगलवार की दोपहर में आतंकवादियों ने बैसरन घाटी में आनंद ले रहे पर्यटकों पर गोलियां बरसाई थीं। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह पहले श्रीनगर और आज पहलगाम पहुंचे थे।

महाराष्ट्र चुनाव कोई गड़बड़ी नहीं...

उम्मीदवारों एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में मतदान प्रक्रिया सम्पन्न हुई। मतदान के बाद कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों द्वारा रिटर्निंग ऑफिसर या पर्यवेक्षकों के समक्ष आधिकारिक रूप से कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। मतदाता सूची के बारे में आयोग ने कहा कि इसे जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 और मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के अनुसार तैयार किया जाता है। प्रतिवर्ष एक विशेष संक्षिप्त समीक्षा कार्यक्रम आयोजित किया जाता है और अंतिम सूची सभी दलों को उपलब्ध करा दी जाती है। केवल 90 अपीलें दायर हुईं इसके अलावा अंतिम सूची जारी होने के बाद केवल 90 अपीलें दायर की गईं, जो कुल मतदाताओं की तुलना में बहुत कम हैं। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस की ओर से भी कोई बड़ी शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। मतदान प्रक्रिया के दौरान सभी दलों द्वारा एक लाख से अधिक मतदान केन्द्रों पर 97,325 मतदान केन्द्र स्तरीय अधिकारी (बीएलओ) और 1,03,727 मतदान केन्द्र स्तरीय प्रतिनिधि (बीएलए) नियुक्त किए गए। इसमें कांग्रेस के 27,099 बीएलए शामिल थे। इसलिए, आयोग ने स्पष्ट किया कि मतदाता सूची के संबंध में आरोप पूरी तरह से निराधार और कानून का उल्लंघन हैं। जनता में भ्रम पैदा करना अनुचित चुनाव आयोग ने 24 दिसंबर 2024 को कांग्रेस को लिखित जवाब दिया है और यह जानकारी आयोग की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। फिर भी आयोग ने कहा है कि बार-बार ऐसे आरोप लगाकर जनता में भ्रम पैदा करना अनुचित है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के परिणाम लोकसभा से बिल्कुल उलट आए थे। विधानसभा चुनावों में सत्तारूढ़ महायुक्ति को न सिर्फ जीत मिली थी बल्कि प्रचंड जीत मिली थी। बीजेपी ने अपने बूते पर 132 सीटें जीती थीं तो वहीं कांग्रेस की अगुवाई वाली महाविकास आघाड़ी (एमवीए) 46 सीटों पर सिमट गया था।

धर्म पूछकर पर्यटकों को मारा...

निरुपम ने पहलगाम घटना के विरोध में मुंबई में पाकिस्तान का झंडा जलाया। यह धिनौना चेहरा है.... संजय निरुपम ने मुंबई के मलाड में शिवसेना के कार्यकर्ताओं के साथ पहलगाम आतंकी हमले के विरोध में पाकिस्तान का झंडा जलाया। शिवसेना नेता ने कहा कि भारत के बेगुनाह और निर्दोष लोगों को धर्म पूछ-पूछकर मारा गया। निरुपम ने कहा कि यह आतंकवाद का धिनौना चेहरा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने घर में घुसकर मारना चाहिए। निरुपम ने कहा यह हमारी मांग है। पहलगाम हमले पर निरुपम ने सोशल मीडिया नेवी ऑफिसर विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी की फोटो का साझा करते हुए लिखा था कि यह तस्वीर कलेजा चीर देने वाली है। नवविवाहित जोड़ी हनीमून के लिए कश्मीर गई थी। आतंकवादियों ने पति का नाम पूछा और जब पाया कि यह हिंदू है तो उसकी हत्या कर दी। पहलगाम अटैक: कश्मीर में फंसे पर्यटकों के लिए एक्शन में आए फडणवीस, हेलपलाइन पर संपर्क करने की अपील निरुपम बोले-संकल्प मजबूत हुआ निरुपम ने एक्स पर भी पहलगाम हमले की निंदा की है। उन्होंने लिखा है कि निर्दोष पर्यटकों का नाम पूछ-पूछकर आतंकवादियों ने जिस तरह क्रूरता से मारा, उससे पूरा देश गुस्से में है। इन्हें चुन-चुनकर मारा जाना चाहिए। पाकिस्तान में घुसकर मारा जाना चाहिए। धारा 370 हटने के बाद जिस तरह कश्मीर का माहौल सामान्य होता जा रहा है। उससे पड़ोसी देश, ISI और पाकिस्तानी फौज द्वारा पोषित आतंकवादी गिरोह लंबे समय से परेशान थे। हमारा संकल्प आतंकवाद का पूर्णतया सफाया है।

मुंबई के मानखुर्द में

महानगर पालिका द्वारा जारी बयान में कहा गया, "शताब्दी अस्पताल से प्राप्त जानकारी के अनुसार, खुशी खान (10) को मृत अवस्था में अस्पताल लाया गया था, जबकि फराह खान (25) को 70 प्रतिशत जलने की गंभीर स्थिति में भर्ती किया गया था, जिसने मंगलवार सुबह आखिरी सांस ली।" प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, मानखुर्द मंडला में हनुमान मंदिर के पीछे जनता नगर में सिलेंडर विस्फोट के कारण आग लग गई। आग पर लगभग 8:40 बजे काबू पा लिया गया। मुंबई फायर ब्रिगेड के अलावा स्थानीय पुलिस, एम्बुलेंस सेवा और वार्ड कर्मियों को भी घटनास्थल पर बुलाया गया।

हमले के बाद कैसा हो भारत का जवाब ! चर्चा के लिए राजनाथ सिंह ने सैन्य अधिकारियों के साथ की बैठक

बैठक में पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत की प्रतिक्रिया पर चर्चा हुई। बैठक में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के हालात पर भी बात हुई और रक्षा मंत्री ने सुरक्षा इंतजाम कड़े करने के निर्देश दिए। जिस जगह हमला हुआ, उसके आसपास भी सैनिकों की तैनाती बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं।

पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद बुधवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा मंत्रालय में अहम बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में सीडीएस अनिल चौहान और एनएसए अजित डोभाल भी शामिल हुए। इनके अलावा बैठक में थल सेना अध्यक्ष जनरल उपेंद्र द्विवेदी, वायुसेना चीफ एयर चीफ मार्शल एपी सिंह और नौसेना प्रमुख दिनेश त्रिपाठी भी मौजूद रहे। बैठक में पहलगाम आतंकी



हमले के जवाब में भारत की प्रतिक्रिया पर चर्चा हुई। बैठक में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के हालात पर भी बात हुई और रक्षा मंत्री ने सुरक्षा इंतजाम कड़े करने के निर्देश दिए। जिस जगह हमला हुआ, उसके आसपास भी सैनिकों की तैनाती बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि जल्द से जल्द हमलावरों को पकड़ा जा सके।

बुधवार शाम छह बजे सुरक्षा मामलों की केंद्रीय समिति की बैठक होनी है। रक्षा मंत्री की बैठक में सीसीएस की बैठक को लेकर भी चर्चा हुई। यह बैठक करीब तीन घंटे चली। मंगलवार को पहलगाम आतंकी हमले को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पर साझा पोस्ट में लिखा कि 'पहलगाम में हुए आतंकी

हमले से वे बेहद व्यथित हैं। मासूम नागरिकों पर यह कारगरना हमला है। मासूम नागरिकों और उनके परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं।'

पहलगाम में हुआ आतंकी हमला पर्यटकों पर 25 साल का सबसे बड़ा हमला

जम्मू कश्मीर के पहलगाम के बैसारन इलाके में मंगलवार को हुए आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की निर्मम हत्या कर दी गई। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, चार से पांच आतंकीयों ने पर्यटकों पर अंधाधुंध गोलीबारी की। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा से जुड़े टीआरएफ ने ली है। पहलगाम का आतंकी हमला बीते 25 साल में पर्यटकों पर हुआ सबसे बड़ा आतंकी हमला बताया जा रहा है।

मालदा के सिकंदरपुर गांव में रात्रि पहरा दे रहे युवक की बेरहमी से हत्या; इंग्लिश बाजार में तनाव



पश्चिम बंगाल के मालदा जिले के इंग्लिश बाजार विधानसभा क्षेत्र के अमृत क्षेत्र के सिकंदरपुर गांव में मंगलवार रात को पहला दे रहे दो युवकों पर कुछ लोगों ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया। इसमें एक युवक की मौत हो गई जबकि दूसरे युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अस्पताल में भर्ती युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। घटना को लेकर ग्रामिणों में जबरदस्त हंगामा किया और पूरे इलाके को जाम कर दिया है। इलाके में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल के साथ ही रैफ को उतारा गया है। मृतक की पहचान शिबू मंडल और घायल की पहचान सूर्य मंडल के रूप में हुई है।

जानकारी के मुताबिक वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए गांव के लोगों ने पहरा देने का निर्यण लिया था। मंगलवार रात को शिबू मंडल और सूर्य मंडल पहरा दे रहे थे। रात को बदमाशों ने उन पर हमला बोल दिया। धारदार हथियार से दोनों पर हमला बोल दिया। इसमें शिबू मंडल की मौत हो गई जबकि सूर्य मंडल की स्थिति गंभीर बनी हुई है।

न्यायपालिका के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी का मामला, हाईकोर्ट ने महिला को सुनाई जेल की सजा



बॉम्बे उच्च न्यायालय ने बुधवार को एक महिला को अदालत की अवमानना का दोषी ठहराते हुए जेल की सजा सुनाई है। दरअसल दोषी महिला ने अदालत को डॉंग माफिया बताया था। अदालत ने इसे अपमानजनक मानते हुए कहा कि एक शिक्षित व्यक्ति से इस तरह की टिप्पणी बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस अद्वैत सेठना की पीठ ने विनीता श्रीनंदन को अदालत की अवमानना का दोषी मानते हुए एक सप्ताह साधारण जेल की सजा और 20 हजार रुपये का आर्थिक दंड लगाने का आदेश दिया।

क्या है मामला

दरअसल नवी मुंबई की एक हाउसिंग सोसाइटी और सोसाइटी की एक निवासी लीला वर्मा के बीच विवाद हुआ था। इस विवाद के चलते लीला वर्मा ने उच्च न्यायालय का रुख किया और आरोप लगाया कि आवारा कुत्तों को खाना खिलाने के चलते हाउसिंग सोसाइटी की प्रबंध समिति द्वारा उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। उच्च न्यायालय ने कहा कि अगर सोसाइटी की प्रबंध समिति को आवारा कुत्तों को खाना खिलाए जाने से नाराजगी है तो उन्हें नगर निगम को इसकी सूचना देनी चाहिए थी न कि खुद ही निवासी का उत्पीड़न करना चाहिए था।

याचिकाकर्ता ने दिया कानून का हवाला

याचिकाकर्ता लीला वर्मा ने कहा कि कानून के तहत रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन और अपार्टमेंट ओनर एसोसिएशन को आवारा कुत्तों को अपने परिसर में खाना खिलाने की मंजूरी देनी चाहिए। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों को भी निर्देश है कि आवारा कुत्तों को खाना खिलाने के लिए तय जगह होनी चाहिए।

कश्मीर में चुनौती बने हैं 76 आतंकी, इनमें अफगानिस्तान फ्रंट पर ट्रेड 55 पाकिस्तानी

जम्मू-कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में लगभग 76 आतंकी छिपे हैं। इनमें से अधिकांश दहशतगर्दों की ट्रेनिंग 'अफगानिस्तान' फ्रंट पर हुई है। इन सभी आतंकीयों तक पहुंचाना, सुरक्षा बलों के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। पहलगाम हमले में भी दो विदेशी यानी पाकिस्तानी आतंकी बताए जा रहे हैं। जेएंडके के विभिन्न हिस्सों में सक्रिय दहशतगर्दों में से 55 पाकिस्तानी हैं तो 21 लोकल बताए जा रहे हैं। पिछले दो वर्षों के दौरान इन दहशतगर्दों ने सुरक्षा बलों को बड़ी चोट पहुंचाई है। आर्मी और जेकेपी के कई अफसर और जवान शहीद हो चुके हैं। विश्वस्त सूत्रों के अनुसार, जब तक ये आतंकी मौजूद हैं, तब तक घाटी से आतंकी हमलों को खत्म कर पाना मुश्किल है। इन आतंकीयों को भरपूर लोकल स्पॉट मिल रही है। इसी के बल पर ये आतंकी, बड़े हमले को अंजाम देने में कामयाब हो जाते हैं।

बता दें कि गत वर्षों में जम्मू-कश्मीर के विभिन्न इलाकों में सुरक्षा बलों और आतंकीयों के बीच कई बड़ी मुठभेड़ हुई हैं। राजौरी के बाजीमाल इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकीवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में सेना के कैप्टन एमवी प्रांजल, कैप्टन



शुभम और हवलदार माजिद सहित चार शहादत हुई थी। राजौरी मुठभेड़ में जो दो आतंकी मारे गए थे, उनमें से एक पाकिस्तानी आतंकी 'क्वारी' भी था। वह पाकिस्तान के आतंकी संगठन 'लश्कर ए तैयबा' का हाई रैंक टेरोरिस्ट था। उसे पाकिस्तान/अफगानिस्तान फ्रंट पर ट्रेड किया गया था। गत दो वर्ष के दौरान, जेएंडके में जितनी भी बड़ी मुठभेड़ हुई हैं, उनमें ज्यादातर हाई रैंक वाले ट्रेड आतंकी मारे गए हैं। सितंबर 2023 में अनंतनाग जिले के कोकरनाग क्षेत्र में हुई मुठभेड़ में भारतीय सेना की राष्ट्रीय राइफल (कर्मल) मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष और जम्मू कश्मीर पुलिस के डीएसपी हुमायूं भट्ट शहीद हो गए थे। इस मुठभेड़ में दो अन्य जवानों ने भी

शहादत दी। साल 2020 के बाद जम्मू-कश्मीर में यह पहली घटना थी, जिसमें सेना के कमांडिंग अफसर शहीद हुए थे।

सूत्रों का कहना है कि भले ही सीमा पर कोई बड़ी घुसपैठ नहीं हुई है, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान की तरफ से बॉर्डर क्रॉस कर आतंकी, जेएंडके में पहुंचे हैं। सुरक्षा बलों द्वारा बॉर्डर पर घुसपैठ के कई प्रयास असफल किए गए हैं। नेपाल का मार्ग, आतंकीयों के भारत में प्रवेश करने का एंट्री प्वाइंट तो नहीं बन रहा, ये बात सुरक्षा एजेंसियों के दिमाग में है। जेएंडके में मौजूदा समय में सत्तर से अधिक आतंकी सक्रिय बताए जाते हैं। उनके पास सुरक्षा बलों की आवाजाही से लेकर कई दूसरे इनपुट तक मौजूद रहे हैं। कोकरनाग क्षेत्र में छिपे दो आतंकीयों तक पहुंचने में

सुरक्षा बलों को लंबा वक्त लगा था। आतंकीयों ने अपने छिपने के लिए ऐसी लोकेशन तैयार की थी, जहां तक सुरक्षा बलों का पहुंचना, आसान नहीं था। इस तरह की रणनीति लोकल आतंकी तैयार नहीं कर सकते। कई वर्षों से घाटी में छिपे हैं दहशतगर्द 2014 के दौरान जेएंडके में 104 आतंकवादी मारे गए थे। 2015 में 97, 2016 में 140, 2017 में 210, 2018 में 257, 2019 में 157, 2020 में 221, 2021 में 180, 2022 में 187, 2023 में 76 और पिछले साल 75 आतंकवादी मारे गए थे। पाकिस्तान की इंटरलिजेंस एजेंसी आईएसआई, अपने गुप्त आतंकी संगठनों की मदद से जम्मू कश्मीर में हाइब्रिड आतंकीयों की भर्ती कर रही है। घाटी में हाल-फिलहाल में कोई बड़ी घुसपैठ नहीं हुई है।

संभव है कि सभी विदेशी आतंकी कई वर्षों से घाटी में कहीं पर छिपे हों। सुरक्षा बलों की वहां तक पहुंच न हो सकी हो। जम्मू कश्मीर पुलिस, आईबी, आर्मी एवं अन्य एजेंसियां आतंकीयों के ठिकाने तक पहुंचने का प्रयास कर रही हैं। इन आतंकीयों को घाटी में किसी न किसी तरह की मदद तो मिल ही रही है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता।

शिक्षकों का आंदोलन तेज, ममता बोलीं- काम पर लौटिए, वेतन की व्यवस्था करेंगे; मुर्शिदाबाद भी जाएंगी

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लगभग 26,000 शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियां रद्द कर दी गईं, जिसके बाद हजारों शिक्षक सड़क पर उतर आए हैं और WBSSC मुख्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।

पश्चिम बंगाल में शिक्षक भर्ती विवाद अब और तेज हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लगभग 26,000 शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियां रद्द कर दी गईं, जिसके बाद हजारों शिक्षक सड़क पर उतर आए हैं और वेस्ट बंगाल स्कूल सर्विस कमिशन (WBSSC) मुख्यालय के बाहर लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि आयोग यह स्पष्ट करे कि किसे मेरिट के आधार पर चुना गया और किसे घूस देकर नियुक्त किया गया।

सीएम ममता बनर्जी ने प्रदर्शनकारियों से की अपील पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को उन शिक्षकों से काम पर लौटने की अपील की। साथ ही भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार उनके वेतन की रक्षा करेगी और उनकी नौकरी भी अभी सुरक्षित है। ममता



बनर्जी ने मिदनापुर में एक सरकारी कार्यक्रम के दौरान कहा आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि कौन दागी है और कौन नहीं। इसकी जिम्मेदारी अदालत और सरकार की है।

ममता बनर्जी ने आगे कहा कि आप बस ये सोचिए कि आपकी नौकरी बनी हुई है और आपको समय पर वेतन मिलेगा। उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं। कृपया अपने स्कूल वापस जाएं और पढ़ाई फिर से शुरू करें। मैं इस मुद्दे पर लगातार बात कर रही हूं। आपकी नौकरी फिलहाल सुरक्षित है। इसके साथ ही ममता बनर्जी ने यह भी घोषणा की कि वह मई के पहले सप्ताह में मुर्शिदाबाद के अशांत क्षेत्रों का दौरा करेंगी।

राज्य शिक्षा मंत्री ने दिया आश्वासन बढ़ते मामले को देखते हुए राज्य के शिक्षा मंत्री ने भी कहा कि योग्य

और अयोग्य उम्मीदवारों की सूची जल्द ही जारी की जाएगी। उन्होंने कहा कि दो सप्ताह में यह सूची प्रकाशित कर दी जाएगी। ब्रत्य बसु ने आगे कहा कि प्रदर्शनकारियों से कहा कि हमें ऐसे कदम उठाने के लिए मजबूर न करें जो सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दायर की जाने वाली समीक्षा याचिका को कमजोर कर दें। गौरतलब है कि चिलचिलाती धूप में करीब 2,000 से अधिक प्रदर्शनकारी एसएससी मुख्यालय के बाहर जमा हो गए। उन्होंने आयोग के अध्यक्ष सिद्धार्थ मजूमदार को भी इमारत के अंदर रोक लिया। प्रदर्शनकारी योग्यता के आधार पर भर्ती किए गए उम्मीदवारों की सूची जारी करने की मांग कर रहे हैं, साथ ही उन आरोपों की जांच करने की भी मांग कर रहे हैं, जिनके तहत कुछ उम्मीदवारों ने कथित तौर पर रिश्वत देकर नौकरी पाई थी।

प्रदर्शनकारी शिक्षकों का आरोप कुछ शिक्षकों ने आरोप लगाया कि वे कई वर्षों से सेवा दे रहे हैं और अब उन्हें अचानक अयोग्य कहा जा रहा है, जिससे उनका भविष्य अंधकारमय हो गया है। साथ ही विरोध कर रहे शिक्षकों का ये भी कहना है कि जब तक उन्हें न्याय नहीं मिलेगा, तब तक वे अपना आंदोलन जारी रखेंगे।

प्रदर्शनकारियों में एक ने अपनी व्यथा बताते हुए कहा कि हमें अब कुछ भी खोने को नहीं है। हमारा आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता। साथ ही एक अन्य प्रदर्शनकारी ने कहा कि अगर हमें खुले आसमान में भूखा रहना पड़ता है, तो वे लोग जो एसी कमरों में बैठे हैं, उन्हें भी हमारी गर्मी महसूस करनी चाहिए। भाजपा सांसद ने प्रदर्शनकारियों का किया समर्थन वहीं भाजपा सांसद अभिजीत गंगोपाध्याय ने भी आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता होनी चाहिए और शिक्षकों को गुमराह नहीं किया जाना चाहिए। देखा जाए तो अब सबकी नजरें सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार द्वारा दायर की जाने वाली समीक्षा याचिका और आयोग द्वारा सूची जारी किए जाने पर टिकी हैं।

गुजरात के अमरेली में प्रशिक्षण विमान दुर्घटनाग्रस्त



अमरेली के पुलिस अधीक्षक संजय खराट ने बताया कि विमान दोपहर करीब 12:30 बजे अमरेली शहर के गिरिया रोड इलाके में एक रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे प्रशिक्षु पायलट की मौत पर ही मौत हो गई।

गुजरात के अमरेली में प्रशिक्षण विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की खबर है। पुलिस ने बताया कि हादसे में पायलट की मौत हो गई है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि एक निजी विमानन अकादमी का प्रशिक्षण विमान मंगलवार दोपहर गुजरात के अमरेली जिले के एक रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया और उसमें आग लग गई। हादसे में एक प्रशिक्षु पायलट की मौत हो गई। बताया गया कि विमान एक पेड़ से टकराकर जमीन पर जा गिरा।

अमरेली के पुलिस अधीक्षक संजय खराट ने बताया कि विमान दोपहर करीब 12:30 बजे अमरेली शहर के गिरिया रोड इलाके में एक रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे प्रशिक्षु पायलट की मौत पर ही मौत हो गई। हादसे के कारण का अब तक पता नहीं चल सका है। उन्होंने बताया कि पायलट अकेले उड़ान भर रहा था। विमान ने अमरेली हवाई अड्डे से उड़ान भरी थी।

खराट ने बताया कि शास्त्री नगर इलाके के पास दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद विमान में आग लग गई और वह लपटों में घिर गया। खराट ने कहा, 'अमरेली हवाई अड्डे से एक पुरुष प्रशिक्षु पायलट के साथ उड़ान भरने के बाद हवाई अड्डे से संचालित होने वाली एक विमानन अकादमी का प्रशिक्षक विमान एक रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अकेले उड़ान भर रहे प्रशिक्षु पायलट की दुर्घटना में मौत हो गई, जबकि विमान जलकर खाक हो गया। दुर्घटना में कोई और घायल नहीं हुआ।'

वक्फ कानून लागू करने को लेकर ममता पर बरसे किरें रिजिजू, कहा- संसद से पारित कानून को रोक नहीं सकता

केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरें रिजिजू ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। केंद्रीय मंत्री ने वक्फ कानून न लागू करने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि कोई भी राज्य संसद से पारित कानून को रोक नहीं सकता है।

केंद्रीय मंत्री किरें रिजिजू ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर वक्फ (संशोधन) अधिनियम को लागू करने से इनकार करने को लेकर पलटवार करते हुए कहा कि संघीय ढांचे के तहत कोई राज्य संसद की तरफ से पारित कानून को रोक नहीं सकता है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने कहा- कुछ गुमराह मुसलमान और वोट बैंक के तुष्टीकरण में लगे राजनेता वक्फ (संशोधन) अधिनियम



का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही इन तत्वों को बेनकाब करेगी।

ममता ने राज्य में वक्फ एक्ट न लागू करने की कही थी बात बता दें कि, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पहले कहा था कि पश्चिम बंगाल में वक्फ अधिनियम लागू नहीं किया जाएगा और वह अल्पसंख्यकों और उनकी संपत्तियों की रक्षा करेंगी।

उनकी टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया देते हुए अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने कहा, 'हम संघीय ढांचे के तहत काम करते हैं। वह सैद्धांतिक रूप से अधिनियम का विरोध कर सकती हैं, लेकिन वह यह नहीं कह सकती कि वह राज्य में संसद की तरफ से पारित कानून को लागू नहीं करेंगी।' मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर भी सीएम ममता पर बरसे रिजिजू उन्होंने वक्फ अधिनियम को

लेकर मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के लिए भी टीएमसी प्रमुख की आलोचना की। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय के कई सदस्य वक्फ अधिनियम लागू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देने के लिए आगे आए हैं।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए नियम बनाए जाएंगे कि वक्फ संपत्तियों का इस्तेमाल गरीब मुसलमानों के कल्याण के लिए किया जाए।

गरीब मुसलमानों को लूटने वाले होंगे बेनकाब- रिजिजू उन्होंने आगे कहा, 'हम जल्द ही उन लोगों को बेनकाब करेंगे जिन्होंने गरीब मुसलमानों को लूटा और उन्हें कानून के प्रावधानों के बारे में गुमराह किया।

जेपीसी अध्यक्ष पीपी चौधरी बोले 17 मई से राज्यों का दौरा, जनता से सीधे मांगे जाएंगे सुझाव



वक्फ कानून के बाद 'एक देश, एक चुनाव' को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) 17 मई से देशभर के राज्यों का दौरा शुरू करने जा रही है। समिति सबसे पहले 17-18 मई को महाराष्ट्र का दौरा करेगी। इसके बाद 19-21 मई तक उत्तराखंड, और जून में जम्मू-कश्मीर, चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा का दौरा किया जाएगा। इस बात की जानकारी जेपीसी के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने मंगलवार को दी। उन्होंने कहा कि समिति की राय है कि इस मुद्दे पर हमें पूरे देश से विचार जानने चाहिए। इसके लिए समिति सभी राज्यों का दौरा करने वाली है करेगी।

भाजपा ने राहुल पर साधा निशाना, कहा- हेराल्ड मामले से ध्यान भटकाने के लिए कर रहे हैं EC पर हमला

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मंगलवार को निर्वाचन आयोग पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी की आलोचना करते हुए इसे 'नेशनल हेराल्ड' मामले से ध्यान भटकाने का प्रयास करार दिया।

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रवक्ता नलिन कोहली ने मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की चुनाव आयोग पर की गई टिप्पणी की कड़ी आलोचना की है। नलिन कोहली ने राहुल गांधी पर रेशनल हेराल्ड मामले से ध्यान हटाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। भाजपा प्रवक्ता नलिन कोहली ने यहां पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में गांधी परिवार पर इस मुद्दे पर चुप्पी साधने का आरोप भी लगाया। कोहली ने कहा, गांधी परिवार ने नेशनल हेराल्ड मामले पर पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है, जबकि दूसरी ओर (पी) चिदंबरम जैसे वरिष्ठ कांग्रेस नेता बचाव में दलीलें पेश करने में जुटे हैं।



उन्होंने आरोप लगाया, निर्वाचन आयोग, भारत में लोकतंत्र और चुनावों के आयोजन को लेकर राहुल गांधी की टिप्पणी यह साबित करती है कि कांग्रेस देश की संस्थाओं पर हमला करके नेशनल हेराल्ड मामले से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। कोहली ने कहा कि चुनाव आयोग का रिकॉर्ड बेदाग है और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाद्रा सहित कई लोग चुनाव जीते हैं। भाजपा प्रवक्ता ने कहा, नेहरू-

गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक एवं व्यक्तिगत हितों के लिए भारत की संस्थाओं पर भी निशाना साधने को तैयार हैं। राहुल ने पिछले रविवार को अमेरिका में एक कार्यक्रम में निर्वाचन आयोग पर "समझौता कर लेने" का आरोप लगाया था। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत के आंकड़ों का हवाला देते हुए निर्वाचन आयोग पर हमला किया था, जिसे लेकर

सत्तारूढ़ भाजपा ने कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए उन्हें "देशद्रोही" बताया था। कांग्रेस ने भाजपा पर साधा निशाना

वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के सोशल मीडिया विभाग की अध्यक्ष और पार्टी प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने मंगलवार को कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) देश के सामने मौजूद महत्वपूर्ण मुद्दों और अपनी विफलताओं से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए नेशनल हेराल्ड मामले में तथ्यों को तोड़-मरोड़कर पेश कर रही है। कांग्रेस नेता ने कहा, हाल के कांग्रेस के ऐतिहासिक गुजरात अधिवेशन से बौखलाए मोदी-शाह की जोड़ी ने फिर से पार्टी पर प्रवर्तन निदेशालय को छोड़ दिया है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दाखिल तथाकथित आरोपपत्र कुछ और नहीं बल्कि विशुद्ध राजनीतिक षड़यंत्र है।

पेगासस पर 29 अप्रैल को 'सुप्रीम' सुनवाई, जानें क्या है इस्राइली सॉफ्टवेयर से फोन हैकिंग का मामला

इस्राइली सॉफ्टवेयर से फोन हैकिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट 29 अप्रैल को सुनवाई करेगी। बता दें कि, पेगासस जासूसी मामले में दायर याचिकाओं में पत्रकारों समेत कई अन्य अनधिकृत निगरानी के आरोपों की जांच की मांग की गई है।

सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस जासूसी मामले में दायर याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 29 अप्रैल की तारीख तय की है। इन याचिकाओं में पत्रकारों और अन्य नागरिकों की अनधिकृत निगरानी के आरोपों की जांच की मांग की गई है।

क्या है मामला? पेगासस एक इस्राइली सॉफ्टवेयर है जिसे मोबाइल फोन को हैक कर निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जाता है।

2021 में कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि भारत में पत्रकारों, नेताओं, और सामाजिक



कार्यकर्ताओं के फोन की जासूसी की गई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की स्वतंत्र जांच के आदेश दिए थे।

पेगासस मामले में कोर्ट की पिछली कार्रवाई 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस मामले की जांच के लिए एक तकनीकी समिति और एक निगरानी समिति बनाई थी। तकनीकी समिति में साइबर सुरक्षा, डिजिटल फॉरेंसिक और नेटवर्क विशेषज्ञ - नवीन कुमार चौधरी, प्रभाहरण पी और अश्विन

अनिल गुमास्ते शामिल थे। वहीं इस जांच की निगरानी पूर्व न्यायाधीश आर वी रवींद्रन कर रहे थे, जिनकी सहायता पूर्व आईपीएस अधिकारी आलोक जोशी और साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ संदीप ओबेरॉय कर रहे थे। जांच में क्या पाया गया? मामले में साल 2022 में अदालत को सौंपी गई रिपोर्ट के अनुसार, 29 में से पांच मोबाइल फोन में मैलवेयर मिला। लेकिन यह तय नहीं हो पाया कि वह पेगासस था या नहीं। अदालत ने यह भी कहा

कि केंद्र सरकार ने जांच में पूरा सहयोग नहीं किया।

याचिकाकर्ताओं की नाराजगी आज की सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील श्याम दीवान ने अदालत को बताया कि अभी तक तकनीकी समिति की रिपोर्ट याचिकाकर्ताओं को नहीं दी गई है, जबकि कोर्ट पहले इसके लिए निर्देश दे चुकी है। उन्होंने इस मामले को जल्दी सुनने की मांग की।

इस मामले की सुनवाई के लिए समय की कमी के कारण जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने अब यह मामला अगले सप्ताह यानी 29 अप्रैल को सुनने का आदेश दिया। समिति की सिफारिशें तीन भागों में तैयार की गई रिपोर्ट में एक भाग में यह सुझाव दिया गया है कि नागरिकों की निजता के अधिकार की रक्षा के लिए कानूनों में बदलाव किया जाए।

भारतीय बैंकों पर US टैरिफ का सीमित असर; 2025 की पहली तिमाही में श्रीलंकाई निर्यात 6% बढ़ने की आस



एक वैश्विक रेटिंग एजेंसी का अनुमान है कि अमेरिकी टैरिफ कदमों का भारतीय बैंकों पर सीमित प्रभाव होगा। मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस की तरफ से जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के विविधीकृत और कम निर्यात के कारण देश के बैंकों पर अमेरिकी टैरिफ कदमों का सीमित प्रभाव पड़ेगा। रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी पूंजीगत व्यय, मध्यम आय वर्ग के लिए कर कटौती और उपभोग को बढ़ावा देने के लिए मौद्रिक ढील देना अहम फैसला है। ऐसे कारकों के आधार पर ही भारतीय बैंकिंग प्रणाली पर उसका दृष्टिकोण स्थिर बना हुआ है। 2025 की पहली तिमाही में श्रीलंकाई निर्यात 6% बढ़ने का अनुमान श्रीलंका के निर्यात विकास बोर्ड का अनुमान है कि 2025 की पहली तिमाही में श्रीलंका के निर्यात में लगभग 6 फीसदी की वृद्धि दर्ज की जाएगी। बोर्ड ने बुधवार को जारी बयान में कहा, 2025 की पहली तिमाही के दौरान श्रीलंका की अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय लचीलापन और वृद्धि दिखी है। देश का कुल निर्यात 4,212.13 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है। पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 5.87 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई है। मार्च में वस्तु और सेवा दोनों सहित कुल निर्यात 1,507.90 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया। निर्यात विकास बोर्ड ने कहा, वर्तमान में मार्च 2024 की तुलना में साल-दर-साल 6.24 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि हो रही है। फरवरी 2025 से महीने-दर-महीने 11.76 प्रतिशत की पर्याप्त वृद्धि दर्ज की गई है।

रेपो रेट में कटौती से निजी खपत बढ़ेगी; एमपीसी के दौरान आरबीआई गवर्नर ने की थी टिप्पणी, मिनट्स जारी

नीतिगत दरों में कटौती से निजी खपत को बढ़ावा मिलेगा और निजी कॉरपोरेट निवेश में सुधार होगा। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने इस महीने की शुरुआत में मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक में यह बात कही। इस दौरान



मल्होत्रा और एमपीसी के पांच अन्य सदस्यों ने रेपो रेट में 0.25 प्रतिशत कटौती के पक्ष में मतदान किया था। गवर्नर मल्होत्रा की अध्यक्षता वाली एमपीसी ने नौ अप्रैल को अल्पकालिक उधारी दर यानी रेपो में 0.25 प्रतिशत की कटौती कर इसे छह प्रतिशत कर दिया था। फरवरी में भी इतनी कटौती की गई थी। आरबीआई ने बुधवार को एमपीसी बैठक का ब्योरा जारी किया। इसमें कहा गया है, "जब उपभोक्ता कीमतों पर आधारित मुद्रास्फीति निर्णायक रूप से चार प्रतिशत के अपने लक्षित स्तर के आसपास है और वृद्धि अभी भी सामान्य है तथा इसमें सुधार हो रहा है, तो ऐसे में मौद्रिक नीति को वृद्धि की गति तेज करने के लिए घरेलू मांग को समर्थन देना चाहिए।"

मल्होत्रा ने बैठक में कहा कि इससे निजी खपत बढ़ेगी और निजी कॉरपोरेट निवेश में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि वृद्धि-मुद्रास्फीति के उभरते रुझानों को देखते हुए आगे भी मौद्रिक नीति को उदार होना चाहिए। एमपीसी की अगली बैठक चार-छह जून, 2025 को होनी है।

आतंकी हमले पर हार्दिक-कमिंस ने जताया दुख, काली पट्टी बांधकर उतरे खिलाड़ी; रखा मौन



जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने के लिए मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच आईपीएल 2025 मैच के दौरान खिलाड़ी और अंपायर काली पट्टी बांधकर मैदान पर उतरे। मंगलवार को हुए इस हमले में 26 लोगों की मौत हुई है जिसमें दो विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) इस घटना से काफी दुखी है और हैदराबाद और मुंबई के बीच बुधवार को मैच से पहले पीड़ितों की श्रद्धांजलि दी गई। कमिंस-पांड्या ने जताया दुख

टॉस के वक्त हैदराबाद के कप्तान पैट कमिंस और मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या काली पट्टी बांधकर उतरे। मुंबई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। कप्तान पांड्या ने कहा- मैं सबसे पहले आतंकवादी हमले के पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूँ। हम एक टीम और एक फ्रैंचाइजी के रूप में ऐसे किसी भी हमले की निंदा करते हैं। वहीं, पैट कमिंस ने भी इस हमले पर दुख जताते हुए कहा- यह हमारे लिए भी दिल दहला देने वाला है, हमारी संवेदनाएं पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं। मैच शुरू होने से पहले रखा गया

मौन मैच के दौरान जहां दोनों टीमों के खिलाड़ी और अंपायर काली पट्टी बांधकर उतरे, वहीं मैच शुरू होने से पहले एक मिनट का मौन भी रखा गया। इतना ही नहीं इस मैच के लिए मैदान पर कोई चीयरलीडर्स भी नहीं होंगी। खेल जगत के लोगों ने पहलगाम आतंकी हमले पर दुख जताते हुए पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। इस आतंकी हमले के बाद कई पूर्व खिलाड़ियों ने सोशल मीडिया पर पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी है। मरने वालों में ज्यादातर पर्यटक जम्मू-कश्मीर के पहलगाम शहर के निकट 'मिनी स्विटजरलैंड' नाम से मशहूर पर्यटन स्थल पर मंगलवार दोपहर हुए आतंकवादी हमले में 26 लोगों की मौत हो गई, जिनमें ज्यादातर पर्यटक हैं। यह 2019 में पुलवामा में हुए हमले के बाद घाटी में हुआ सबसे घातक हमला है। पहलगाम शहर से लगभग छह किलोमीटर दूर बैसरन चीड़ के पेड़ों के घने जंगलों और पहाड़ों से घिरा एक विशाल घास का मैदान है तथा देश व दुनिया के पर्यटकों के बीच पसंदीदा स्थान है। पहलगाम हमले के संबंध में अधिकारियों और प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि हथियारबंद आतंकवादी 'मिनी स्विटजरलैंड' में घुस आए और भोजनालयों के आसपास घूम रहे, खच्चर की सवारी कर रहे, पिकनिक मना रहे पर्यटकों पर गोलीबारी शुरू कर दी। पाकिस्तान में स्थित प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी) के छद्म संगठन 'द रेजिस्टेंस फ्रंट' (टीआरएफ) ने हमले की जिम्मेदारी ली है।

'तू कौन, तेरी औकात क्या...?' पहलगाम हमले को लेकर किस पर क्यों बरसे जावेद अख्तर



पहलगाम में मंगलवार (22 अप्रैल 2025) को हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। इस हमले में 26 मासूम लोगों की जान चली गई और कई अन्य घायल हुए। इस जघन्य घटना के बाद जहां पूरा देश शोक और गुस्से में है। वहीं, मशहूर गीतकार और लेखक जावेद अख्तर ने सोशल मीडिया पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी। हालांकि, उनकी पोस्ट पर कुछ लोगों के आपत्तिजनक कमेंट्स ने उन्हें नाराज कर दिया। जावेद अख्तर ने ऐसे लोगों को एक्स पर करारा दिया है। पहलगाम हमले के बाद जावेद अख्तर ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर ट्वीट किया, 'रचाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, पहलगाम के आतंकीयों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जा सकता। इन सामूहिक हत्यारों को उनके अमानवीय कृत्यों की सजा अपनी जान देकर चुकानी होगी।' इस ट्वीट में जावेद ने आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए देश की एकजुटता का आह्वान किया, लेकिन कुछ लोगों ने उनके इस बयान पर आपत्तिजनक टिप्पणियां कीं, जिससे जावेद का गुस्सा भड़क उठा।

'तू कौन, तेरी औकात क्या?'

एक शख्स ने जावेद के ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा, 'आज नहीं, आज नहीं, चुप रह, हमें तेरी सहानुभूति नहीं चाहिए।' इस टिप्पणी से नाराज जावेद ने तुरंत पलटवार किया। उन्होंने लिखा, 'रतू कौन, तेरी औकात क्या? मुझे तुझसे कोई सहानुभूति नहीं चाहिए। भाग जा तू,

दिलों को झकझोर देने वाले पहलगाम हमले पर श्रेया घोषाल का पोस्ट, लिखा, 'मैं भुला नहीं पा रही'



जम्मू कश्मीर के पहलगाम में बीते मंगलवार को हुए आतंकी हमला से पूरा देश सहम गया है। इस मामले में कई मासूम लोगों की

जाने गई। उन्हें बड़ी ही बेदर्दी से सरेआम मार दिया गया। उनका दुख और तकलीफ आज किसी भी भीरतीय के लिए गहरा सदमा है। इस दर्दनाक घटना पर कई सेलेब्स ने दुख जताया और सोशल मीडिया के जरिए अपनी राय व्यक्त की हैं। वहीं श्रेया घोषाल ने भी अपना दर्द सोशल मीडिया के जरिए शेयर किया है। श्रेया घोषाल ने कुछ ही देर पहले इंस्टाग्राम पर पहलगाम हमले पर अपनी राय शेयर करते हुए लिखा, 'मैं पहलगाम पर हुए हमले के बारे में सोचना नहीं छोड़ पा रही हूँ। उन परिवारों की जिंदगी अब पहले जैसी नहीं हो पाएगी।' उन जिंदगियों का हिंसा से क्या लेना-देना- श्रेया आगे श्रेया ने लिखा, 'मेरा दिल टूट गया जब मुझे पता चला कि इतनी खूबसूरत और शांत जगह पर कई जाने गईं, मुझे लगता है कि उन जिंदगियों का हिंसा से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी इसका शिकार बन गए।'

'कोई बहाना नहीं चलेगा', ऋषभ पंत पर भड़के अंबाती रायडू; लताड़ लगाकर की ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी की मांग

पूर्व भारतीय बल्लेबाज और मशहूर कमेंटेटर अंबाती रायडू ने लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के कप्तान ऋषभ पंत के मौजूदा फॉर्म पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि पंत को अपने फैसलों पर नियंत्रण करना चाहिए और ऊपरी क्रम में आने के लिए बहाने बंद करने होंगे। मंगलवार को दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ मुकाबले में लखनऊ को आठ विकेट से मुंह की खानी पड़ी थी। इस मैच में स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज सातवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए थे, जिसकी वजह से अब उन्हें आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली के खिलाफ खाता खोले बिना लौटे पंत मौजूदा सत्र में पंत का बल्ला खामोश रहा है। अब तक खेले नौ मैचों में उन्होंने सिर्फ 106 रन बनाए हैं, इनमें सिर्फ एक अर्धशतकीय पारी शामिल है। दिल्ली के खिलाफ वह सातवें नंबर पर बल्लेबाजी के लिए आए बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। उन्हें मुकेश कुमार ने बोलड किया। यह मुकाबले में शिकस्त के साथ लखनऊ - 0.054 के नेट रन रेट के साथ पांचवें पायदान पर खिसक गई।



मैच के बाद अंबाती रायडू ने ऋषभ पंत पर अपनी भड़ास निकाली और कहा कि उन्हें टीम में लिए जाने वाले निर्णयों पर नियंत्रण रखना होगा और ऊपरी क्रम में बल्लेबाजी के लिए आना होगा। उन्होंने कहा- ऋषभ पंत को वास्तव में एलएसजी में लिए जा रहे निर्णयों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। उसे बल्लेबाजी क्रम में ऊपर आने की आवश्यकता है। वह अब कोई बहाना नहीं दे सकता। वह कप्तान है और यह कप्तान का खेल है। हम सभी इसे स्वीकार करते हैं। आगे बढ़ते हुए, एलएसजी को कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। शायद मयंक यादव को शामिल किया जाए। साथ ही पंत को थोड़ा

ऊपर बल्लेबाजी करनी होगी। आप पूरी स्थिति को लेकर स्पष्ट रूप से काफी तनाव में दिख रहे हैं। अंतिम ओवर में बल्लेबाजी के लिए उतरे पंत पंत बल्लेबाजी के लिए उस वक्त उतरे जब लखनऊ की पारी समाप्त होने में दो गेंद शेष थी। पंत इस मैच में भले ही दो गेंद खेलने उतरे, लेकिन खाता भी नहीं खोल सके। लखनऊ की पारी समाप्त होने के बाद ड्रेसिंग रूम में निराश नजर आए। सबसे ज्यादा हैरानी की बात पंत का निचले क्रम पर उतरना रहा। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि सातवें नंबर पर उतरने का फैसला पंत का था या टीम प्रबंधन ने उन्हें देर से उतरने कहा था।

जहीर खान से पंत की बहस पर भी बोले रायडू मैच के बाद पंत टीम के मेंटर जहीर खान के साथ तीखी बहस करते नजर आए। ऐसा लग रहा था कि वह जहीर के साथ बल्लेबाजी स्थान को लेकर बहस कर रहे हैं। इस पर चर्चा करते हुए रायडू ने कहा- मुझे लगता है कि पंत को वास्तव में खुद पर जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। उसे वास्तव में अपने फैसले खुद लेने की जरूरत है। अगर आप एक अच्छी टीम हैं तो कभी-कभी ये दृश्य वास्तव में अच्छे नहीं होते हैं। क्योंकि आप चाहते हैं कि सब कुछ बंद दरवाजों के पीछे हो। आप चाहते हैं कि सब कुछ घर के अंदर कहा जाए।

तेज धूप में गन्ने का जूस पीने के हैं कई नुकसान, जानिए सेवन का सही समय और तरीका

गर्मी के मौसम में शरीर को ठंडक और ऊर्जा देने के लिए गन्ने का रस एक उपयोगी पेय है। गन्ने का जूस सेहत के लिए काफी फायदेमंद भी माना जाता है। इस मौसम में भारत में तो चौराहे और नुककड़ों पर गन्ने का रस आसानी से मिल जाता है। चिलचिलाती गर्मी से राहत पाने के लिए लोग गन्ने का रस पीना पसंद करते हैं। लोगों को लगता है कि पानी के बजाय गन्ने का जूस पीने से स्वास्थ्य लाभ भी होगा और प्यास भी बुझेगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तेज धूप में गन्ने का रस पीना सेहत को नुकसान भी पहुंचा सकता है। इसे पीने का समय और तरीका सही न हो, तो यह फायदे की जगह

नुकसान भी पहुंचा सकता है। आइए जानते हैं तेज धूप में गन्ने का जूस पीने के नुकसान क्या हैं और इसे पीने का सही समय और तरीका क्या है। तेज धूप में गन्ने का जूस पीने के नुकसान चिलचिलाती धूप में शरीर पहले से गर्म होता है। ऐसे में गन्ने का ठंडा रस पीने से पाचन तंत्र पर असर पड़ सकता है, जिससे गैस, अपच या पेट में ऐंठन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। गन्ने का रस प्राकृतिक रूप से ठंडा होता है। गर्मी में पसीने से भीगा शरीर जब अचानक ठंडी चीज लेता है, तो इससे गला खराब हो सकता है या सर्दी-खांसी हो सकती है।



खुले में बिकने वाले गन्ने के जूस में हाइजीन की कमी हो सकती है। तेज धूप में गन्ने को खुले में रखना बैक्टीरिया पनपने का कारण बनता है, जिससे फूड पॉइजनिंग या पेट की इन्फेक्शन हो सकती है। गन्ने में प्राकृतिक शक्कर अधिक

होती है। धूप में थके हुए शरीर में इसे तुरंत पीने से शुगर लेवल अचानक बढ़ सकता है, जिससे चक्कर या थकान महसूस हो सकती है। गन्ने का रस पीने का सही समय गन्ने का रस सुबह या दोपहर के समय पी सकते हैं, लेकिन धूप से

आने के तुरंत बाद इसका सेवन न करें। छांव या ठंडी जगह पर बैठकर जूस पिएं, ताकि शरीर का तापमान थोड़ा सामान्य हो जाए। खाली पेट गन्ने के रस का सेवन न करें। हल्का नाश्ता करने के बाद ही

इसे पीएं। गन्ने के रस से मिलने वाले स्वास्थ्य लाभ को लेना है तो हाइजीन वाले जूस सेंटर से ही इसे लेकर पीएं या घर पर बनाकर पिएं। गन्ने का रस पीने का सही तरीका गन्ने के जूस में नींबू और काला नमक मिलाकर पिएं, इससे पाचन अच्छा रहता है। जूस को हमेशा ताजे गन्ने से बना हुआ ही पिएं। जूस पीने के बाद सीधे धूप में न जाएं, कुछ देर आराम करें। ध्यान रखें कि ठंडा जूस भले ही गर्मी में राहत देता हो लेकिन बहुत अधिक ठंडा गन्ने का रस गले में दर्द और जुकाम का कारण बन सकता है। इसलिए गन्ने का रस बहुत अधिक ठंडा न हो।

यूएस-इस्राइल-रूस-जर्मनी-इटली जैसे देशों ने दिया भारत का साथ; दुनियाभर के नेताओं ने की निंदा



जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की निंदा दुनिया भर के नेताओं ने की है। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, इस्राइल के विदेश मंत्री गिदोन सा'आर समेत कई ने शोक जताया है। अमेरिका भारत के साथ खड़ा है- ट्रंप वहीं इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्विथ सोशल पर लिखा- 'कश्मीर से बहुत परेशान करने वाली खबर आई है। आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ अमेरिका मजबूती से खड़ा है। हम मारे गए लोगों की आत्मा की शांति और घायलों के स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और भारत के अविश्वसनीय लोगों को हमारा पूरा समर्थन और गहरी सहानुभूति है। हमारी संवेदनाएं आप सभी के साथ हैं।' जेडी वेंस ने आतंकी हमले पर

जताई संवेदना वहीं भारत के दौरे पर आए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने इस पर शोक जताते हुए एक्स पर लिखा, 'उषा और मैं भारत के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। पिछले कुछ दिनों में, हम इस देश और इसके लोगों की खूबसूरती से अभिभूत हैं। इस भयावह हमले पर शोक जताते हुए हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं उनके साथ हैं।' व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट ने कहा, 'राष्ट्रपति को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की तरफ से जानकारी दी गई है और जैसे-जैसे और तथ्य सामने आ रहे हैं, उन्हें जानकारी दी जा रही है। हम पहले से ही जानते हैं कि दक्षिण कश्मीर के एक लोकप्रिय पर्यटक स्थल पर हुए क्रूर आतंकवादी हमले में दर्जनों लोग मारे गए और इससे भी ज्यादा लोग घायल हुए। राष्ट्रपति ट्रंप जल्द से जल्द

प्रधानमंत्री मोदी से बात करेंगे और मारे गए लोगों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना व्यक्त करेंगे और हमारी प्रार्थनाएं घायलों के साथ हैं और हमारे देश का समर्थन हमारे मित्र भारत के साथ है। आतंकवादियों की तरफ से की जाने वाली इस तरह की भयावह घटनाओं के कारण ही हममें से जो लोग दुनिया में शांति और स्थिरता के लिए काम करते हैं, वे अपना मिशन जारी रखते हैं।' पुतिन ने पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुर्मु को लिखा शोक संदेश रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले पर राष्ट्रपति ट्रंप को मुर्मु और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं। रूस दूतावास ने राष्ट्रपति पुतिन के हवाले से लिखा- कृपया पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के दुखद परिणामों पर अपनी संवेदनाएं स्वीकार करें, जिसके शिकार नागरिक थे - कई देशों के नागरिक। इस क्रूर अपराध का कोई औचित्य नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि इसके जिम्मेदारों और अपराधियों को उचित सजा मिलेगी। मैं आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों से

लड़ने में भारतीय भागीदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराना चाहूंगा। कृपया मृतकों के निकट और प्रियजनों के प्रति अपनी सहानुभूति और समर्थन व्यक्त करें, साथ ही सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करें।' वहीं भारत में रूस के राजदूत डेनिस अलीपोव ने ट्वीट कर लिखा, 'पहलगाम में पर्यटकों पर हुए जघन्य आतंकवादी हमले पर भारत के लोगों और सरकार के प्रति गहरी संवेदना। रूस पूरी तरह से भारत के साथ खड़ा है।' यूएई ने आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की वहीं संयुक्त अरब अमीरात ने जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों को निशाना बनाकर किए गए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की है, जिसमें कई लोग मारे गए और कई निर्दोष लोग घायल हुए। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में पुष्टि की कि यूएई इन आपराधिक कृत्यों की कड़ी निंदा करता है और अंतर्राष्ट्रीय कानून के उल्लंघन में सुरक्षा और स्थिरता को कमजोर करने के उद्देश्य से हिंसा और आतंकवाद के सभी रूपों को स्थायी रूप से अस्वीकार करता है।

जम्मू- कश्मीर में आतंक मचा रहीं दर्जनभर तंजीमें, सीमा पार के आतंकी संगठनों का हैं मुखौटा



जम्मू-कश्मीर में पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों की फेहरिस्त बढ़ती जा रही है। पहले जेएंडे में 'लश्कर-ए-तैयबा' (एलईटी), जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) और हिजबुल मुजाहिदीन जैसे बड़े संगठन खुद आतंकी हमलों को अंजाम देते थे। अब इन संगठनों ने जम्मू कश्मीर में अपनी-अपनी प्रॉक्सी विंग खड़ी कर ली हैं। ये संगठन, पाकिस्तान में बैठकर छोटे समूहों के द्वारा जेएंडे के हमले की रणनीति को अंजाम देते हैं। घाटी में आतंकियों की नई भर्ती कमजोर पड़ने की वजह से अब ये संगठन, ओवर ग्राउंड वर्कर और सलीपर सेल की मदद ले रहे हैं। 2019 के बाद खासतौर से, छोटे आतंकी समूह 'पीएफएफ' और 'टीआरएफ' ने जम्मू कश्मीर में अपना नेटवर्क स्थापित कर लिया है। इन दोनों संगठनों ने भारतीय सेना, सीएपीएफ और जेकेपी को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। सुरक्षा एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक, 'पीएफएफ' और 'टीआरएफ' का जाल, जेएंडे के अधिकांश हिस्सों में फैल चुका है। पाकिस्तान के आतंकी संगठन 'लश्कर-ए-तैयबा' (एलईटी) और जैश-ए-मोहम्मद (जेईएम) ने जम्मू-कश्मीर में अपने सहयोगी समूह 'प्रॉक्सी विंग' खड़े किए हैं। जैश-ए-मोहम्मद की प्रॉक्सी विंग, 'पीपुल्स एंटी-फासिस्ट फ्रंट' (पीएफएफ) है, जबकि 'द रेजिस्टेंस फ्रंट' (टीआरएफ), 'लश्कर-ए-तैयबा' की 'प्रॉक्सी विंग' है। खास बात है कि इन दोनों 'प्रॉक्सी विंग' को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आतंकी संगठनों की सूची में शामिल कर रखा है। इन दोनों समूहों के लिए काम कर रहे ओवर ग्राउंड वर्करों को पकड़ने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस और एनआईए सक्रिय है। एनआईए ने आतंकी फंडिंग और ओवर ग्राउंड वर्करों की जड़ों तक पहुंचने के लिए कई बार घाटी में रेड की है। इसके तहत कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं। तकनीकी उपकरण भी बरामद किए गए हैं। जम्मू कश्मीर में उक्त आतंकी संगठनों के अलावा कई दूसरी तंजीमें भी सक्रिय हैं।

पहलगाम हमले के जिम्मेदार अमित शाह', संजय राउत ने सरकार पर साधा निशाना

मुंबई: कश्मीर के पहलगाम जिले स्थित बैसरन घाटी में आतंकी हमले में हिंदू पर्यटकों की नृशंस हत्या के कारण पूरे देश में जबरदस्त आक्रोश है। आम जनता के साथ-साथ राजनीति से जुड़े लोग भी सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन सियासी लोग हमले के लिए खासकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उनके गृह मंत्रालय को हमले का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। पहलगाम हमले के लिए अमित शाह को जिम्मेदार ठहराते हुए शिवसेना यूबीटी पार्टी के

सांसद व प्रवक्ता संजय राउत सहित पूरा विपक्ष अमित शाह पर हमला कर रहा है। संजय राउत ने भाजपा की नफरत की राजनीति तथा गृह मंत्री अमित शाह के मातहत काम करनेवाले खुफिया विभाग को निष्क्रियता को दोषी ठहराते हुए अमित शाह के इस्तीफे की मांग की। विपक्ष को जेल भेजने में व्यस्त सरकार अमित शाह को विफल गृह मंत्री बताते हुए संजय राउत ने कहा कि आतंकियों ने हमले से पहले लोगों की धार्मिक पहचान पृष्ठ के बाद गोली मारी थी। इसके लिए



बीजेपी की नफरत भरी राजनीति दोषी है। उन्होंने आरोप लगाया कि

यह नफरत पश्चिम बंगाल से जम्मू-कश्मीर तक फैल रही है।

संजय राउत ने केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सत्ताधारी नेता सरकारें बनाने-गिराने और विपक्षियों को जेल भेजने में व्यस्त हैं, जिससे आम लोगों की सुरक्षा भगवान भरोसे है। उन्होंने यह भी दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी को आतंकवाद खत्म करने का उपाय बताया था, लेकिन आतंकी हमले बढ़ रहे हैं। कांग्रेस ने सरकार को ठहराया जिम्मेदार पहलगाम आतंकी हमले में विधानसभा में कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा इतने बड़े हमले

के बारे में खुफिया विभाग को जानकारी नहीं मिली? यह सुरक्षा प्रणाली की विफलता है। पर्यटकों के आसपास कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी, सरकार को इसके लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा यह पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी हमला है और इस हमले को अंजाम देने वाले आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए तथा आतंकवाद का स्थायी रूप से सफाया किया जाना चाहिए।

अजित पवार ने JK सीएम उमर अब्दुल्ला से फोन पर की बात, टूरिस्टों की वापसी पर दिया अपडेट

मुंबई: जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में बीते दिन हुए आतंकवादी हमले में 28 लोगों की जान चली गई। पहलगाम (जम्मू-कश्मीर) में हुए आतंकवादी हमले के बाद राज्य सरकार जम्मू-कश्मीर गए महाराष्ट्र के पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा उन्हें सुरक्षित राज्य में वापस लाने के लिए प्रयास कर रही है। इस संबंध में महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से फोन पर बात की। पहलगाम आतंकी हमले के बाद अजित पवार ने उमर अब्दुल्ला से महाराष्ट्र के पर्यटकों को तत्काल सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया। अजित पवार ने कहा है कि हमारी प्राथमिकता प्रत्येक पर्यटक को सुरक्षित वापस घर लाना तथा उनके परिवारों को राहत प्रदान करना है। आप घबराए नहीं - अजित पवार



अजित पवार ने कहा इस बीच, मंत्रालय के आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ में विशेष अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी, जो फंसे हुए पर्यटकों से समन्वय स्थापित करेंगे तथा उन्हें आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे। कश्मीर में फंसे पर्यटकों के परिजनों से अपील है कि वे घबराएं नहीं। केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोले से भी संपर्क किया जा रहा है तथा विशेष हवाई सेवाएं प्रदान करने की योजना बनाई जा रही है।

अधिक से अधिक उड़ानें भेजकर पर्यटकों की शीघ्र तथा सुरक्षित वापसी की व्यवस्था की जाएगी। स्थिति पर कड़ी निगरानी राज्य सरकार ने जिला प्रशासन, पर्यटन विभाग तथा आपातकालीन प्रबंधन एजेंसियों को अलर्ट पर रखा है तथा स्थिति पर कड़ी निगरानी रख रही है। हमले में मारे गए महाराष्ट्र के नागरिकों के शवों को तत्काल राज्य में लाया गया है, घायलों को आवश्यक उपचार दिया गया है तथा संबंधित एजेंसियों को पर्यटन स्थल पर होटलों में फंसे राज्य के नागरिकों को सुरक्षित वापस लाने के निर्देश दिए गए हैं। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने जानकारी दी कि सभी पर्यटकों के नाम की सूची, उनके ठहरने के स्थान तथा संभावित वापसी कार्यक्रम तैयार किए जा रहे हैं तथा इस पूरी प्रक्रिया को समन्वित एवं त्वरित तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।

पार्टी का माहौल बिगाड़ रहे बड़बोले नेता! राज ठाकरे ने मनसे सैनिकों को जमकर लताड़ा



मुंबई: पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की शिवसेना (यूबीटी) से राज ठाकरे की पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) की संभावित युति को लेकर राज्य में अटकलों का बाजार गर्म है। राज-उद्धव के फिर से साथ आने की संभावनाओं की वजह से समर्थक व मराठी भाषी जनता उत्साहित है लेकिन सत्तारूढ़ गठबंधन महायुति के साथ राज की अपनी पार्टी मनसे के कुछ बड़बोले नेता यूबीटी और उद्धव पर हमला बोलकर माहौल बिगाड़ने का प्रयास कर रहे हैं। पार्टी के बड़बोले नेताओं को राज ने साफ शब्दों में 29 तक चुप रहने का निर्देश दे दिया है। यूबीटी से गठबंधन को लेकर उद्धव गुट के साथ-साथ राज ठाकरे भी गंभीर नजर आ रहे हैं।

विरोध के बाद झुकी महाराष्ट्र सरकार, हिंदी को लेकर बदला फैसला, नहीं होगी अनिवार्य भाषा

मुंबई: महाराष्ट्र सरकार ने कक्षा 1 से 5वीं तक की पढ़ाई में हिंदी के अनिवार्य करने के फैसले पर रोक लगा दी है। शिक्षा मंत्री दादा भुसे के कहा है कि हिंदी अनिवार्य नहीं रहेगी। लेकिन तीन भाषा सीखना अनिवार्य होगा, जिसमें मराठी और इंग्लिश अनिवार्य है, तीसरी भाषा अब ऑप्शनल होगी। बच्चे तीसरी भाषा अपनी पसंद से चुन सकते हैं। महाराष्ट्र में हिंदी को अनिवार्य करने के मामले पर लगातार

राजनीतिक बहस जारी थी। इस मामले पर सीएम देवेंद्र फडणवीस पर भी दबाव बनाने की कोशिश की गई थी। देवेंद्र फडणवीस ने भी इस मुद्दे पर अपना बयान जारी किया था। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने रविवार को राज्य में हिंदी को थोपने की चिंताओं को खारिज करते हुए कहा था कि मराठी अनिवार्य बनी रहेगी। सीएम फडणवीस ने पुणे में संवाददाताओं से कहा कि ये कहना गलत



है कि हिंदी को थोपने की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र में मराठी अनिवार्य होगी, कोई अन्य बाध्यता नहीं होगी। प्रदेश के मराठी भाषा विभाग की भाषा सलाहकार समिति ने उनसे कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्यता के फैसले को रद्द करने की अपील की थी। क्या कहता है नियम? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि नई शिक्षा नीति कहती है कि

छात्रों को पढ़ाई जाने वाली तीन भाषाओं में से दो भारतीय भाषा होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि भाषाएं सीखना महत्वपूर्ण है। नियम में आगे कहा गया है कि इन तीन भाषाओं में से दो भारतीय होनी चाहिए और मराठी को पहले ही अनिवार्य किया जा रहा है। आप हिंदी, तमिल, मलयालम या गुजराती के अलावा कोई भी अन्य भाषा नहीं ले सकते। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि 'हम ये फैसला लेंगे कि अगर

कोई छात्र हिंदी के अलावा कोई अन्य भाषा सीखना चाहता है तो उसे ऐसा करने की अनुमति दी जाएगी। ये सुविधा एनईपी में भी उपलब्ध है।' सीएम ने आगे कहा कि हालांकि, इसमें एक शर्त होगी कि दूसरी भाषा चुनने वाले छात्रों की संख्या कम से कम 20 होनी चाहिए, तभी वे नया शिक्षक रख पाएंगे। अगर ऐसा नहीं है तो छात्रों को पढ़ाने के लिए वर्चुअल या वैकल्पिक तरीका तलाशा जाएगा।